Linking of Tali Nala with Hooghly

2986. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to link Tali Nala with the Hooghly river for better water transport and irrigation facilities;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any central team has visited some places in the district of South 24 Parganas, West Bengal, recently; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) and (b) while no such proposal has been received at the Centre, the Government of West Bengal has reported constitution of a multi-disciplinary committee to study overall development aspect of Tali Nala.

(c) and (d) A Central Team of Experts visited Sunderbans area of West Bengal between October, 19 to October 22, 1992 and held discussions with officials of the State Government. A broad indicative outline of possible Master Plan for Irrigation, Drainage, Flood Control, Navigation and Pisciculture for benefitting the districts of 24 Parganas South and North was made available for the study and consideration of the team. The proposal was in the form of fund requirement listing out various works amounting *to* Rs. 767 crores. After examination of the proposal Central Water Commission advised the State Government to prepare a detailed and well worked out master plan indicating the need, objectives, and development strategies leading to a plan of action. It was also pointed out that the Master Plan has to follow with Project Reports on specific schemes contained therein with its techno-economic viability and assigned priority.

Sharing of river waters between India and Bangladesh

2987. DR. NARREDDY THULASI REDDY:
SHRI P. UPENDRA:
Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to refer to the answer to U.Q. 366 given in the Rajya Sabha on 10th July, 1992 and state:

(a) whether the talks are still in progress between India and Bangladesh on sharing of waters of Ganga, Teesta and other major rivers;

(b) what is the outcome of the talks held recently in Dhaka; and

(c) by when the talks are likely to be resumed?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) to (c) Talks have been recently held at Delhi November, 1992 at Experts level between Bangladesh and India. Both sides held in-depth discussions to work for an equitable, long-term and comprehensive arrangement for sharing of flows of Ganga, Tista and other major rivers.

Sharing of Yamuna Water among States

2988. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI KAMAL MORARKA:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have lately been working out inter-state agreements for the allocation and development of Yamuna waters, amongst Haryana, U.P., Rajasthan, Himachal Pradesh and the Union Territory of Delhi; and

(b) on what basis the Yamuna Water is sought to be allocated and distributed?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V.C. SHUKLA): (a) Yes Sir. A series of meetings with the Chief Ministers of the Basin States and Lt. Governor of Delhi were convened to find an amicable solution to the

problem and to work out inter-state agreements for the allocation and development of Yamuna waters.

(b) Yamuna water is proposed to be allocated by safeguarding the present utilisation of the Basin States, and allocating the balance waters to meet their drinking water needs.

इज़रायल की पद्धति पर सिंचाई योजना का शुरू किया जाना

2989. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इज़राइल की तरह सिंचाई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस "ड्रिप" योजना की मुख्य विशेषतायें क्या-क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार का बिल्कुल इजरायल पद्धति पर सिंचाई स्कीम लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इज़रायल में व्यापक आधार पर उपयोग की जा रही ड्रिप सिंचाई स्कीम भी जल तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हमारे देश में जोर पकड़ रही है। बागवानी फसल के उत्पादन/उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान 15.55 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। कृषि मंत्रालय ने लघु/सीमान्त कृषकों जिसमें लघु/सीमान्त कपास उगाने वाले खेतिहरों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली शामिल है को सहायता देने के कार्यक्रम के अंतर्गत कई स्कीमों को शुरू करने के वास्ते राज्य सरकारों को 500 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

कृष्णा-कोयना परियोजना का पूरा किया जाना

2990. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृष्णा-कोयना परियोजना को पूरा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) मार्च, 1992 के अन्त तक कृष्णा-कोयना लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर 293.27 करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत के मुकाबले 36.81 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए 75 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। वर्ष 1992-93 के दौरान संभावित व्यय 9.38 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए 30 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।

बिहार को सिंचाई राशि का आबंटन

2991. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में सिंचाई राशि बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) बिहार सरकार से, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु केन्द्र में कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्र में यह निर्णय किया गया है कि राज्यों की वार्षिक योजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं के लिए किये गए प्रावधान का सख्ती से प्रबोधन किया जाए ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

Issuance of Irrigation Bonds

2992. SHRI VISHNU KANT SHASTRI:
SHRI RAM RATAN RAM:
DR. NAUNIHAL SINGH:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have not agreed to the request of Maharashtra and other State Governments for issue of irrigation bonds; and